

सम्पादकीय

राहत की दरकार

का के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री के संवाद के लिये बैठक बुलाई गई थी। मगर बाद में इसमें पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई का मुद्दा हावी हो गया। प्रधानमंत्री का कहना था कि विपक्षी दलों शासित राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क घटाने के बावजूद वैट छम्बे कटौती करके पेट्रोल-डीजल उपभोक्ताओं को राहत नहीं दी। इसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। कंग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र से राजग सरकार के दौरान बढ़ाए गये उत्पाद शुल्क को घटाकर महंगाई कम करने की मांग की है। यह सर्वविविधत है कि कोरोना संकट के लागभग दो वर्ष के दौरान तमाम लोगों की आय में गिरावट आई है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों को आम जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार दिखाना चाहिए। समाज में कमोबेश हर वर्ग की आय में संकुचन हुआ है। हालिया अंकड़ों के अनुसार करीब चार करोड़ लोग उच्च मध्यम वर्ग से निम्न मध्यम वर्ग में आ गये। जब तक आय के नये अवसर बनें और रोजगार संकट खत्म हो सके, तब तक सरकारों को किसी न किसी तरह राहत देने की पहल करनी चाहिए। इससे जब लोगों की आय बढ़ेगी तो वे स्वतंत्र ही सरकार की छूट के लिये नहीं देखेंगे। राज्य सरकारों को वैट में कमी करके अपनी आय के दूसरे स्रोत तलाशने चाहिए। साथ ही जीएसटी के संग्रहण में जो छिप्र हैं उन्हें बंद करके अपनी आय बढ़ानी चाहिए। दरअसल, केंद्र सरकार ने बीते साल नवंबर में उत्पाद शुल्क को कम करके राज्य सरकारों से पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट घटाने का आग्रह किया था। भाजपा शासित राज्यों ने तो इसमें अपनी सुविधा के अनुसार कमी कर दी थी, लेकिन कंग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों वाली सरकारों मसलन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखण्ड तथा तमिलनाडु ने वैट में कमी करके उपभोक्ताओं को राहत नहीं दी। जैसा कि जाहिन था कंग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान के बाद तीखे हमले किये। कंग्रेस ने मांग की कि पहले राजग सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट के दौरान बढ़ाये गये अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करके राहत दे। साथ ही दलील दी कि यूपी शासन के दौरान हर साल एक लाख करोड़ की सब्सिडी दी जाती रही है। जबाब में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मामलों के मंत्री सरकार के बचाव में उत्तर। उनकी दलील थी कि भाजपा शासित राज्यों के मुकाबले दूसरे दलों की सरकारों में पेट्रोल व डीजल पर वैट की दर करीब दुगनी है, जिसे लोगों को राहत देने के लिये कम किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि राज्यों की सरकारों को अन्य मर्दों से अतिरिक्त आय जुटानी चाहिए। यह कटु सत्य है कि देश करीब अस्सी फीसदी कच्चा तेल विदेशों से मंगवाता है। फिर राज्यों के पेट्रोल पंपों के जारी इसकी खुदरा बिक्री होती है। लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि मूल खरीद मूल्य के मुकाबले करीब दुगने मूल्यों पर इसकी खुदरा बिक्री होती है। दरअसल, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल दाम में उत्पाद शुल्क, वैल्यू एडेंड टैक्स यानी वैट मिलाकर इसकी अंतिम कीमत का निर्धारण होता है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाला वैट राज्य सरकारों की आय का मुख्य जरिया है। साथ ही अन्य मुख्य आय स्रोतों में शराब व संपत्ति पर लगने वाला कर है। जीएसटी से पहले आय केंद्र को होती है और फिर राज्यों को उनका हिस्सा दिया जाता है, जिसके बंतवारे व समय पर न मिलने को लेकर केंद्र व राज्यों में लगातार तनातनी रही है। सही मायनों में पेट्रोलियम पदार्थों की आर्थिकी को राज्य अपनी कामधेनु मानते हैं और इसमें कटौती को आसानी से तैयार नहीं होते। बहरहाल, केंद्र सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों, पर्यावरण प्रदूषण व सेहत से जुड़े मुद्दों पर पूरे देश के लिये एक नीति निर्धारित कर आम आदमी को राहत देने का प्रयास करना चाहिए।

भी कुछ संकेत ऐसे मिले हैं, जिनसे है कि पाकिस्तान की विदेश नीति में हिस्से का पैसा लगाने में बेहद हीले-उसने 2000 मेगावाट के बिजलीघर

जामक बंदरगाह तक 1153

पारवतना का लाभ उठाकर भारत आर पाकिस्तान अपने आपसी संबंध काफी सुधार सकते हैं। जिस चीन से पाकिस्तान अपनी 'इस्पाती दोस्ती' का दावा करता रहा है, वह इस्पात अब पिघलता दिखाई पड़ रहा है। जो चीन 5 लाख करोड़ रु. खर्च करके पाकिस्तान में तरह-तरह के निर्माण-कार्य कर रहा था, उस प्रयोजना का भविष्य खटाई में पड़ गया है। चीन अपने शिनच्यांग प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर नामक बंदरगाह तक 1153 किमी लंबी सड़क बना रहा था ताकि अरब और अफ्रीकी देशों तक पहुंचने का उसे सस्ता और सुगम मार्ग मिल जाए लेकिन अब शाहबाज शरीफ की नई सरकार ने इस पाक-चीन गलियारे की योजना को क्रियान्वित करनेवाले प्राधिकरण को भंग कर दिया है। इसे भंग करने के कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो बलूचिस्तान में से इस गलियारे की लंबाई 870 किमी है, जो कि सबसे ज्यादा है। बलूच लोग इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। उन्होंने दर्जनों चीनी कामगारों को मार डाला है। दूसरा, इसने बहुत वक्त खींच लिया है। इसके कई काम अधूरे पड़े हुए हैं। तीसरा कारण यह भी है कि पाकिस्तान अपने

गवादर नामक बंदरगाह तक 1153 किमी लंबी सड़क बना रहा था ताकि अरब और अफ्रीकी देशों तक पहुंचने का उसे सस्ता और सुगम मार्ग मिल जाए लेकिन अब शाहबाज शरीफ की नई सरकार ने इस पाक-चीन गलियारे की योजना को क्रियान्वित करनेवाले प्राधिकरण को भंग कर दिया है। इसे भंग करने के कई कारण बताए जा रहे हैं। एक तो बलूचिस्तान में से इस गलियारे की लंबाई 870 किमी है, जो कि सबसे ज्यादा है।

ह। इसा तरह शशनच्चाग स ग्वादर तक रलव लाइन डॉलन का 55 हजार करोड़ रु. की प्रायोजना भी खटाई में पड़ गई है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वह कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मालदार मुस्लिम राष्ट्रों के आगे अपनी झोली फैलाने के लिए मजबूर है। ऐसी स्थिति में वह चीन से अगर विमुख होता है तो उसके पास अमेरिका की शरण में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस वक्त तो रूस और चीन दोनों की ही दाल पतली हो रही है। एक की यूक्रेन के कारण और दूसरे की कोरोना के कारण ! अमेरिका तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार रहा है। यदि शाहबाज शरीफ थोड़ी हिम्मत दिखाएं और नई पहल करें तो पाकिस्तान का उद्धार हो सकता है। यदि अमेरिका से उसके संबंध बेहतर होंगे तो भारत के साथ वे अपने आप सुधरेंगे। अमेरिका इस वक्त चीन से बेहद खफा है। उसके इस्पाती दोस्त पाकिस्तान को वह अपनी हथेली पर उठा लेगा। शाहबाज चाहें तो भारत के साथ बंद हुए सभी रास्तों को खोलने की भी कोशिश कर सकते हैं। अमेरिका अपने आप उसके लिए अपनी भुजाएं फैला देगा।

अदाप शु
ब्द सं

वै शाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि को साल भर में पड़े अब्दुल मुहर्रूम में से एक मानी जाती है। बता दें कि अक्षय तृतीया एक संस्कृत शब्द है

जिसका अर्थ है- अक्षय यानी सुख, सफलता, आनंद की कपी कमी न हो और तृतीया यानी तीन। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक काम करना काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन वाहन, प्रपंची आदि के अलावा सोना खरीदना काफी शुभ माना जात है। सोने का खरीदना का अर्थ है कि आने वाला पूरा साल धन और सौभाग्य की प्राप्ति हो। इस साल अक्षय तृतीया पर काफी खास संयोग बन रहा है। जो करीब पांच दशक बाद बन रहा है। दरअसल, इस बार अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र के साथ शोभन योग भी बन रहा है। इसके साथ ही अक्षय तृतीय मंगलवार के दिन होने के कारण रोहिणी योग का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा चंद्रमा और सूर्य उच्च राशि में विराजमान है। जहां चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में होंगे और वहाँ शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में होंगे। इतना ही नहीं गुरु अपनी स्वराशि मीन में और शनि अनी स्वराशि कुंभ में होंगे। ऐसे दुर्लभ संयोग करीब 50 साल बाद हो रहे हैं। यह संयोग काफी मंगलकारी माना जा रहा है। आज के दिन सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके साथ ही दोनों की विधि-विधान से पूजा करें। इसके लिए एक चौकी पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखा जाना चाहिए।

कैसे मिले न्याय, कठघरे में कार्यपालिका और विधायिका

दे श म न्याय व्यवस्था लिंग कर्दर पटरा स उतरा ह यह बात सभा का मालूम है। ऐसे हजारों प्रमाण है कि मुकदमा शुरू होता है, पेशी पर पेशी, पेंडिट और आरोपी की मौत हो जाती है लिंगन फैसला नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में जब भारत के मुख्य न्यायीश देश के मुख्यमन्त्रियों और

मालूम है। ऐसे हजारों प्रमाण हैं कि मुकदमा शुरू होता है, पेशी पर पेशी, पीड़ित और आरोपी की मौत हो जाती है लेकिन फैसला नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में जब भारत के मुख्य न्यायधीश देश के मुख्यमंत्रियों और

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस तरह का टिप्पणी कई बार कर चुके हैं। बहुत ही छोटे छोटे मामलों को न्यायालय की चौखट तक पहुंचाने में स्थानीय पुलिस और प्रशासन की भूमिका बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। नाली, रास्ता, अतिक्रमण जैसे मामले जिनका निस्तारण तहसील दिवस आदि में हो जाना चाहिए वे मामले भी सालों साल जिला न्यायालयों में भटकते रहते हैं। भारत की न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जजों ने कई बार तीखी टिप्पणी की लेकिन इसका असर अब तक नहीं दिखाई पड़ा। आकड़ों पर नजर डाले तो 2010 और 2020 के बीच सभी न्यायालयों में लंबित मामलों में 2.8 प्रतिशत की दूर से तार्किक बढ़तें रही हैं। 15 सितंबर 2021 तक भारत के सभी न्यायालयों में 4.5

आदि में हो जाना चाहिए वे मामले भी सालों साल जिला न्यायालयों में भटकते रहते हैं। भारत की न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जजों ने कई बार तीखी टिप्पणी की लेकिन इसका असर अब तक नहीं दिखाई पड़ा। आकड़ों पर नजर डाले तो 2010 और 2020 के बीच सभी न्यायालयों में लंबित मामलों में 2.8 प्रतिशत की दर से वार्षिक बढ़ोतरी हुई। 15 सितंबर, 2021 तक भारत के सभी न्यायालयों में 4.5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित थे। इनमें 87.6 प्रतिशत मामले अधीनस्थ न्यायालयों और 12.3 प्रतिशत उच्च न्यायालयों में लंबित थे। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई नए मामले दायर नहीं होते तो सर्वोच्च न्यायालय को सभी लंबित मामलों को निपटाने में 1.3 वर्ष लगेंगे और उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों, प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष लगेंगे। 2019 और 2020 के बीच उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों में 20 प्रतिशत की दर से, और अधीनस्थ न्यायालयों में 13 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई। उल्लेखनीय है कि 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण न्यायालयों में सामान्य कामकाज सीमित रहा। इसलिए जहां पिछले वर्षों की तुलना में नए मामले बहुत कम थे, लंबित मामले बढ़ते गए- चूंकि मामलों को निपटाने की दर, दर्ज होने वाले नए मामलों की दर से बहुत धीमी थी। एक चौकाने वाला आकड़ा यह कि लगभग 45 लाख मामले अधीनस्थ और उच्च

न्यायालयों में 10 वर्षों से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। उच्च न्यायालयों में 21 प्रतिशत और अधीनस्थ अदालतों में 8 प्रतिशत मामले 10 वर्षों से ज्यादा समय से लंबित हैं। अब जरा बॉत न्यायाधीशों की कमी पर कर कर ले तो यह भी एक बड़ा कारण है कि न्यायाधीशों की कमी के कारण भी देश में न्याय मिलना कठिन है।

या उन पर मुकदमा चल रहा है) की संख्या बहुत अधिक हो दिसंबर, 2019 तक भारत की जेलों में लागभग 4.8 लाख वै

22,545 नामपक्ष नेता या संसदीय सत्राना ने 3,450 पर जाहा या वह अकेले सरकार ही नहीं है जो इस तरह के दुखद मामलों के लिए जिम्मेदार है। खुद न्यायपालिका को भी नियुक्तियों में देरी के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। ऐसी कई घटनाएं हुईं जहां पर उच्च न्यायालयों ने रिक्त पदों के लिए नामों की सिफारिश करके न्यायाधीशों की नियुक्ति शुरू नहीं की थी। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में 58,700 तथा उच्च न्यायालयों में करीब 44 लाख और जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग तीन करोड़ मुकदमे लिखित हैं। इन कुल लिखित मामलों में से 80 प्रतिशत से अधिक मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में हैं। इसका मुख्य कारण भारत में न्यायालयों की कमी, न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों का कम होना तथा पदों की रिक्तता का होना है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर देश में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 18 न्यायाधीश हैं। विधि आयोग की एक रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या तकरीबन 50 होनी चाहिये। इस विधित तक पहुँचने के लिये पदों की संख्या बढ़ाकर तीन गुना करनी होगी। पिछले दो दशकों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई गई हैं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों और इन फास्ट ट्रैक कर्टेस में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मई 2021 तक 24 राज्योंध्यूटी (बाकी में फास्ट ट्रैक अदालतें चालू हालत में नहीं हैं) में 956 फास्ट ट्रैक अदालतों में 9.2 लाख से अधिक मामले लंबित थे। लंबे समय तक मामले लंबित रहने की वजह से भारत की जेलों में अंडरट्रायल्स (आरोपी व्यक्ति जोकि या तो मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं इन से 3,500 (3.5 लाख) से ज्यादा अंडरट्रायल हैं।

अंडरट्रायल्स पांच वर्ष या उससे अधिक समय से जेलों में बंद हैं। इनमें से करीब आधे अंडरट्रायल उत्तर प्रदेश (2,142) और महाराष्ट्र (394) की जेलों में हैं। यानि ठीक ही कहा गया कि न्याय मिलने में अगर देरी होती है तो वह न्याय नहीं मिलने के समान है। स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान स्वस्थ न्यायपालिका को माना जाता है, लेकिन हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी लचर है कि दो-तीन पीढ़ियां गुजर जाती हैं, फिर भी उहें न्याय नहीं मिल पाता है। कायदे से बदतर हालत की जिम्मेदारी लेकर सरकार को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, पर ज्वलता है वाली मानसिकता उनपर पर होती है। सरकार के सारे कल-पुर्जे बस खींसें निपोरने में ही मशगूल हैं। निश्चित तौर पर छह साल के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, समस्त हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और प्रत्येक राज्य सरकार के मुखियों की कॉफेस में विचारधीन कैदियों, हिन्दी और स्थानीय भाषाओं में फैसले, त्वरित न्याय, गैर जरूरी पुराने कानूनों को निरस्त करने, आपसी समझौते से केसों का निपटाने पर चर्चा की गई। लेकिन इस कर्टेस में जो सबसे बड़ी बात उठी की देश की न्यायालयों में लम्बित 50 प्रतिशत मुकदमों के लिए सरकार जिम्मेदार है इस पर सरकारों को अवश्य मंथन करना होगा। केन्द्र और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब तब फटकार लगाता रहता है, इसके बावजूद अगर कार्यपालिका और विधायिका अपनी जिम्मेदारी का निवहन इसी तरह करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत में गरीबों के लिए न्याय एक दिव्य सपना बना रहेगा। -प्रेम शर्मा

फट रहन

एक्सरसाइज बना ना दे आपको बीमार
छले कछ समय से लोग अपनी फिटनेस के जोड़ों के लिए प्रेरणाती भग हो सकता है।

पको लेकर कुछ अधिक ही सजग हो गए हैं। अब वह अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए खान-पान के साथ-साथ एक्सरसाइज पर भी उतना ही ध्यान देते हैं। यह सच है कि अपने शरीर

का ख्याल रखने के लिए एक्सरसाइज करना आवश्यक है। लेकिन आप फिटनेस के चक्कर में खुद की सेहत के साथ ही खिलाड़ ना कर लें, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मसलन, अगर आप जस्तर से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो यह आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जब आप ओवर एक्सरसाइज करती हैं या फिर बहुत अधिक हार्ड ट्रेनिंग करती हैं, तो आपके पीरियड्स मिस हो सकते हैं। इस स्थिति को एमेनोरिया कहा जाता है। यह एस्ट्रोजन के स्तर में पिरावट के कारण होता है जिससे ऑस्ट्रोपोरोसिस भी हो सकता है। इसलिए ट्रेनिंग करें, लेकिन सोच समझकर। बहुत अधिक एक्सरसाइज आपके शरीर ही एक्सरसाइज करें। जब आप आवश्यकता से अधिक वर्कआउट करते हैं, तो इसका विपरीत प्रभाव आपके स्लीप साइकल पर पड़ता है। आवश्यकता से अधिक व्यायाम करने पर आप थक तो बहुत जाते हैं लेकिन फिर भी आपको नींद आने में समस्या होती है। इतना ही नहीं, थकान व नींद की कमी के चलते आपको अन्य कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन आवश्यकता से अधिक व्यायाम आपके हृदय के लिए भी सही नहीं है। जो लोग ओवर एक्सरसाइज करते हैं। खासतौर से, उच्च तीव्रता वाले व्यायाम करने से हृदय रोगियों को दिल का दौरा या स्ट्रोक से मृत्यु का उच्च जोखिम होता है।

पयटका क लिए धूमन क लिए बहुत कुछ

अलावा यहां पर कुछ बेहतरीन झीलें हैं। ओडिशा की झीलें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं और स्थानीय और पर्यटकों दोनों के लिए दर्शनीय स्थल हैं। चिल्का झील सबसे बड़ी और ओडिशा की सबसे लोकप्रिय झीलों में से एक है। भारत में सबसे बड़ी खेरे पानी की झील है और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है। हर तरफ हरे भेरे जंगलों से घिरा, चिल्का झील पर्यटकों को बर्ड वॉचिंग, पिकनिक, बोटिंग और मछली पकड़ने के लिए बेहतरीन है। चिल्का झील झील की यात्रा के लिए नवंबर से मार्च सही समय है क्योंकि साइबेरिया से बहुत से प्रवासी पक्षी यहां आते हैं। महानदी नदी के किनारे पर स्थित है और सारनदा हिल्स और बिष्णुपुर हिल्स से घिरा हुआ है, अंसुपा झील में आप प्राकृतिक संरक्षित और विट्ठली है, बल्कि इसकी समृद्ध जैव विविधता भी बेहद लोकप्रिय है। आप यहां पर एक बस झील के किनारे बैठकर, शांत वातावरण का आनंद ले सकता है। छतरपुर शहर के पास स्थित, पाटा झील ओडिशा में मीठे पानी की झीलों में से एक है, जो साल भर पर्यटकों द्वारा घूमती है। खूबसूरत परिवेश से लेकर अपनी स्फूर्तिवायक ताजगी के लिए, पाटा झील काफी सुंदर जगह है और स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। यदि आप भुवनेश्वर में हैं, तो कंजिया झील को अपनी सूची में जरूर रखें। शहर के बाहरी इलाकों में स्थित, यह झील 66 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है और इसे प्रमुख जल स्रोत माना जाता है। बनस्पतियों और जीवों की समृद्ध जैव विविधता इसे ओडिशा की प्राकृतिक झील बताती है।

फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण सत-प्रतिशत हो : मनोज

अपर पुलिस अधीक्षक ने किया कोतवाली हैदरगढ़ का निरीक्षण

कैनविज टाइम्स संवाददाता

हैदरगढ़ बाराबंकी। लम्बित पड़ी विवेचनाओं का निस्तारण जल्द से जल्द करें, थाने पर आए हुए फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण सत-प्रतिशत करने के साथ साथ उसका संपूर्ण विवरण रजिस्टर पर अंकित करें उसके बाद वह पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हो। या नहीं इस बारे दूरभास से जरूर जानकारी ले उत्तर वात अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार पांडेय द्वारा थाना कोतवाली हैदरगढ़ के औचक निरीक्षण के दौरान कही। इसके अलावा प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार वर्मा को भी उचित दिशा निर्देश दिए। औचक निरीक्षण दौरान उहाँने शस्त्रागार साफ सफाई रजिस्टर के खरखाल को देखा एवं उचित दिशा निर्देश दिए प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक मनोज



कुमार पांडे लोपहर 2:00 बजे के सम्बंध में भी एसएचओ को निर्देश दिया। इस दौरान मुख्य रूप से प्रधारी निरीक्षक बृजेश कुमार वर्मा वर्षाएँ उप निरीक्षक धनीराम वर्मा कस्बा चौकी इंचार्ज संतोष कुमार राय कहन्हाया कुमार यादव राधेश्याम यादव पूनम पटेल अंजय पाल सिंह योगेंद्र सिंह वीरेंद्र पाल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।

कुमार पांडे लोपहर 2:00 बजे के आसपास कोतवाली हैदरगढ़ पहुंचे जहां उहाँने साफ सफाई देखी तो प्रत्येक पुलिसकर्मी द्वारा थाना परिसर में वृक्षारोपण करने को कहा। इसके बाद विवेचना के संबंध में उप निरीक्षक गणें उचित दिशा निर्देश दिए। उहाँने थाने पे लंबे समय से खड़े वाहनों की नीलामी कराये जाने के

आत्मनिर्भर भारत मिशन से प्रेरित होकर कृषि के क्षेत्र में किस्मत आजमा रहे हैं अनुदेशक आशीष सिंह

कैनविज टाइम्स संवाददाता

हैदरगढ़ बाराबंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन से प्रेरित होकर क्षेत्र के एक शिक्षक पुत्र ने खेती से आत्मनिर्भर बनने का रास्ता निकाला है। जोधपुरी गांव के शिक्षक माता पल्टन सिंह के पुत्र आशीष सिंह ने परंपरागत खेती को छोड़कर कृषि के क्षेत्र में नवीन प्रयास कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में कृषि अनुदेशक के पद पर कार्यरत आशीष सिंह ने अपने शिक्षक साथी स्लिंपीय वर्मा जो स्वयं एक अच्छे किसान है से प्रेरित होकर 2 बीघे खेत में तरबूज की रोपाई की। कृषि स्नातक की पढ़ाई से जो सीखा उसका प्रयोग उहाँने अपने खेतों में शुरू किया है। आशीष कहते हैं कि यिन्हें नीवों से बहुत ही अल्प मानदेश पर अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ लेकिन इन्हें वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार ने हम अनुदेशकों की सुध नहीं ली जबकि हम सरकार से लगातार अनुदेशकों के भविष्य को सुरक्षित करने की



गुहर लगाते रहे हैं कब तक सरकार से उम्मीद लगाए जाएं फिर मैंने अपनी शिक्षा का प्रयोग खेतों में करने का फैसला किया और एक छोटी सी बेड तकनीक से तरबूज की खेती करने से खरपतवार निकालने का खर्च बच जाता है। तरबूज की बुवाई से पहले खेत में ट्रैक्टर की मदद से बेड बनाए जाते हैं और इसके बाद इसमें मल्बंग की बोट भाव और फुटकर भाव में ज्यादा अंतर ना हो इसके साथ ही सरकार द्वारा कृषि के संबंध में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को केवल कुछ किसानों तक ही सीमित न रखा जाए साथ ही साथ विभिन्न अनुदेशकों में नवीन किसानों को भी जड़ा जाए जिससे इसका लाभ ज्यादा किसानों को मिल सके।

तरबूज की बुवाई बेड तकनीक से की है बेड बनाकर उसपर मल्बंग डालकर तरबूज के बीजों की बुवाई की गई है। उहाँने बताया की बेड तकनीक से तरबूज की खेती करने से खरपतवार निकालने का खर्च बच जाता है। तरबूज की बुवाई से पहले खेत में ट्रैक्टर की मदद से बेड बनाए जाते हैं और इसके बाद इसमें मल्बंग

उपजिलाधिकारी ने गेहूं खरीद केन्द्रों का किया मुआयना, पेट्रोल-पम्प भी जाँचा

कैनविज टाइम्स संवाददाता

बाराबंकी। उपजिलाधिकारी के आदेश पर थाना देवा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र गौतम पुत्र अर्जुन गौतम निवारी ग्राम हुसैनामठ थाना देवा जनपद बाराबंकी को निरापद किया गया। अभियुक्त के निशानेही पर दो अद्वालाकल्प द्वारा देवा पुलिस एवं अभियुक्त के निरापद करते हुए उसे न्यायिलय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बताते चले कि अर्जुन गौतम पुत्र स्वरूप कन्वर्ड लाल गौतम निवारी ग्राम हुसैनामठ थाना देवा जनपद बाराबंकी ने अपने छोटे पुत्र द्वारा बड़े पुत्र की हत्या करने के सम्बन्ध में थाना देवा पर तहसील देकर मुकदमा पंजीकृत कराया। उक्त घटना से सम्बन्धित अभियुक्त की



सम्पर्क कर उहाँने खरीद केन्द्रों पर गेहूं बेचने के लिए प्रेरित करने की बात भी उपजिलाधिकारी ने केन्द्र प्रभारियों से उचित दिशानिर्देश दिए। साथ ही उपजिलाधिकारी ने केन्द्र के बैठने और पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र प्रभारियों को उपजिलाधिकारी ने केन्द्र प्रभारियों से साथ ही जाँच की। इस मौके पर खाद्य निरीक्षक हैदरगढ़ संजय कुमार भी उनके कामकाज के बीच हो रही है।

हैदरगढ़ टाउन स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप की खाद्य निरीक्षक हैदरगढ़ के निरापद निवारी ग्राम हुसैनामठ थाना देवा के बीच होने वाले साथ ही साथ उपजिलाधिकारी ने केन्द्र प्रभारियों से साथ ही उपस्थित हो।

सीएचसी पर मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

कैनविज टाइम्स संवाददाता

रामसन होने वाले इंद्रधनुष का उद्घाटन कोविड-19 की चौथी लहर का मार्क ड्रिल करने अपनी टीम के साथ सीएचसी पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गंगीर अवधार में नवजात शिशु का इलाज किया। सामान्य होने पर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। सोमवार को यादवी विकास एवं अधिकारी बाराबंकी राम जी वर्मा जूनियर डायरेक्टर डॉ सोमेंद्र अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव कुमार अपनी टीम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहदौर पर मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्घाटन करने का चक्र तोड़ा गया। सोमवार को यादवी विकास एवं अधिकारी बाराबंकी राम जी वर्मा जूनियर डायरेक्टर डॉ सोमेंद्र अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव कुमार अपनी टीम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहदौर पर मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्घाटन करने का चक्र तोड़ा गया। इसके बाद अस्पताल भेज दिया। सोमवार को यादवी विकास एवं अधिकारी बाराबंकी राम जी वर्मा जूनियर डायरेक्टर डॉ सोमेंद्र अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव कुमार अपनी टीम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहदौर पर मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्घाटन करने का चक्र तोड़ा गया। इसके बाद अस्पताल भेज दिया। सोमवार को यादवी विकास एवं अधिकारी बाराबंकी राम जी वर्मा जूनियर डायरेक्टर डॉ सोमेंद्र अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव कुमार अपनी टीम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहदौर पर मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्घाटन करने का चक्र तोड़ा गया। इसके बाद अस्पताल भेज दिया। सोमवार को यादवी विकास एवं अधिकारी बाराबंकी राम जी वर्मा जूनियर डायरेक्टर डॉ सोमेंद्र अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव कुमार अपनी टीम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहदौर पर मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्घाटन करने का चक्र तोड़ा गया। इसके बाद अस्पताल भेज दिया। सोमवार को यादवी विकास एवं अधिकारी बाराबंकी राम जी वर्मा जूनियर डायरेक्टर डॉ सोमेंद्र अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव कुमार अपनी टीम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहदौर पर मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्घाटन करने का चक्र तोड़ा गया। इसके बाद अस्पताल भेज दिया। सोमवार को यादवी विकास एवं अधिकारी बाराबंकी राम जी वर्मा जूनियर डायरेक्टर डॉ सोमेंद्र अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव कुमार अपनी टीम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहदौर पर मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्घाटन करने का चक्र तोड़ा गया। इसके बाद अस्पताल भेज दिया। सोमवार को यादवी विकास एवं अधिकारी बाराबंकी राम जी वर्मा जूनियर डायरेक्टर डॉ सोमेंद्र अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव कुमार अपनी टीम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहदौर पर मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्घाटन करने का चक्र तोड़ा गया। इसके बाद अस्पताल भेज दिया। सोमवार को यादवी विकास एवं अधिकारी बाराबंकी राम जी वर्मा जूनियर डायरेक्टर डॉ सोमेंद्र अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव कुमार अपनी टीम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहदौर पर मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्घाटन करने का चक्र तोड़ा गया। इसके बाद अस्पताल भेज दिया। सोमवार को यादवी विकास एवं अधिकारी बाराबंकी राम जी वर्मा जूनियर डायरेक्टर डॉ सोमेंद्र अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजीव कुमार अपनी टीम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहदौर पर मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्घाटन करने का चक्र तोड़ा गया। इसके बाद अस्पताल भेज दिया। सोमवार को यादवी विक

